

# Principle of Maximum Social Advantage

## अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त

राज्य के निम्न नीति निर्धारण के अन्तर्गत सरकार आय व लाग सम्बन्धी श्री मुख्य कार्यों को करती है। लेकिन आय को ही लाग का सांभल रखे केस है इसपर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचारधारा है।

प्राचीन विचारधारा के अनुसार सरकार वही आयें मानी जाती हैं जो कग से कग कर लगाती हैं और कग से कग रवर्न करती हैं। इसलिए J.B. Sayy ने कहा कि "सार्वजनिक वित्त की वही योजना सबसे उपयुक्त होती है जिसमें न्यूनतम लाग किया जाता है और सब करों में वही सबसे अच्छा होता है जिसकी मात्रा सबसे कम होती है।"

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार के न सभी कर अभिशाप है और न सभी लाग अनुत्पादक होते हैं। वर्तमान समय में 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना ही मुख्य उद्देश्य है। जिसमें सरकार का आय और लाग दोनों में इस प्रकार का सांभल रखे है कि समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो।

अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। डाल्टन के अनुसार "राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वही कहलायगी जिसकी क्रियाओं में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होती है।" यदि सरकार के किसी कार्य से या कर लेने से कुछ व्यक्ति व्यक्तियों को बुरासाग है पर सम्पूर्ण समाज का कल्याण है तो वह राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार न्यायोचित माना जाता है।

राजस्व के सिद्धान्त के अनुसार सरकार इस प्रकार कर ले तथा उसे व्यय करे कि अनुपयोगिताओं से ऊपर उपयोगिताओं की मात्रा अधिकतम हो।

अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकार की निम्न क्रियाएँ अभिप्राय हैं। -

### 1. आय के वितरण में परिवर्तन -

सरकार कर के रूप में धनी वर्ग के लोगों से आय प्राप्त करती है और उसे मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करती है। इससे आय की असमानता कम होती है जो अधिकतम कल्याण को बढ़ाता है।

### 2. उत्पादन में परिवर्तन -

कर चुकाने के लिए या तो लोग उपभोग कम करते हैं या बचत कम करते हैं जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए प्रजातिशील कर का लगना आवश्यक है।

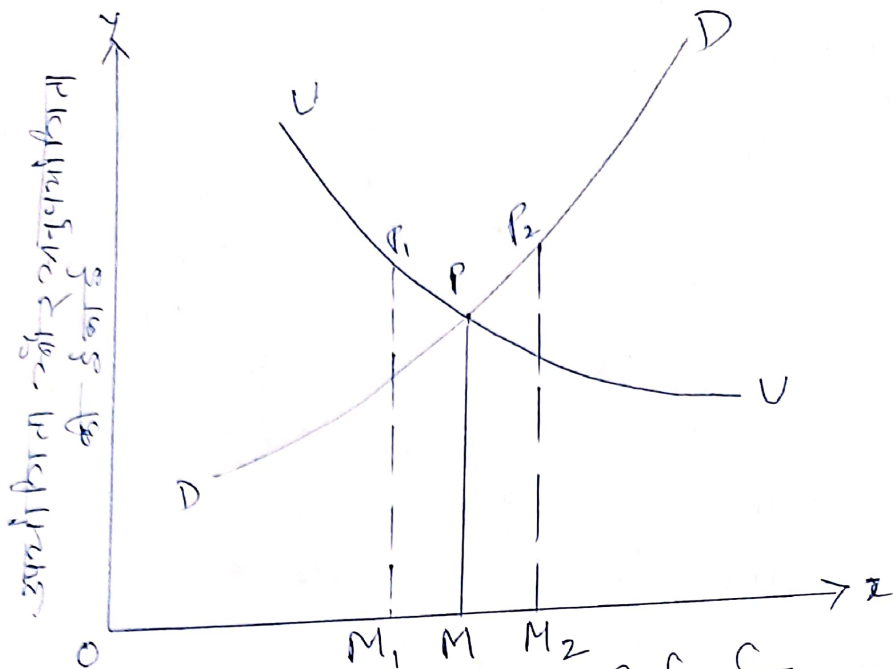
### 3. बचत पर प्रभाव -

अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए यह आवश्यक है कि कर इस प्रकार लगाया जाय जिससे कि समाज में बचत को प्रोत्साहन मिले। अतएव अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उक्त खारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ को सिद्धान्त उपयोगिता प्राप्त निष्पत्ति पर आधारित है। सरकारें प्रायः धनी वर्गों पर उच्च कर लगाती हैं और इनसे प्राप्त होने वाली आय मध्यम वर्गों पर व्यय की जाती है। धनी वर्गों पर करारोपण से उनकी सीमान्त उपयोगिता

घटती है इसी ओर जब इन करो से प्राप्त आय गरीबों की सुव्यवस्था पर खर्च किया जाता है तो इससे उनकी सौगन्त उपयोगिता शुरू में बढ़ती है लेकिन आर्थिक रूप से खर्च होने पर उनकी सौगन्त उपयोगिता घटती शुरू हो जाती है। डाक्टर के अनुसार "यह प्रक्रिया सरकार द्वारा इस सीमा तक प्रचारित करनी चाहिए जब तक बढ़ती हुई सौगन्त उपयोगिता गरीबों की बढ़ती हुई सौगन्त उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती। अधिक कर की मात्रा में बढ़ि से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता कर से प्राप्त रकम की व्यय करने से समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर ~~कर~~ चाहिए। उपर्युक्त सिद्धान्त को गणनीयता तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

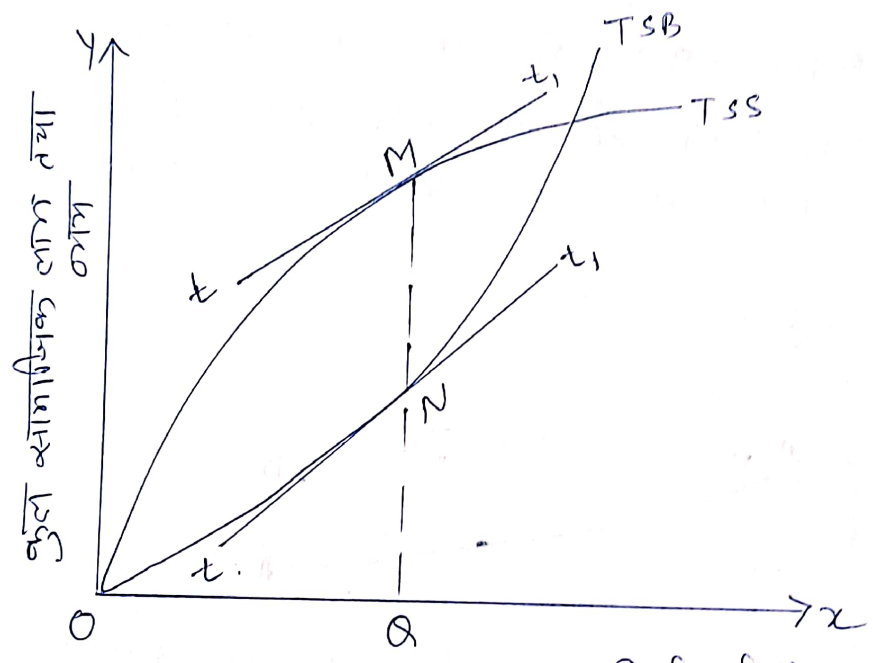
इकाई	करावण से होने वाली अनुपयोगिता	कर से प्राप्त रकम की व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता
1	1	36
2	4	28
3	8	24
4	12	22
<u>5</u>	<u>19</u>	<u>19</u>
6	26	7
7	34	2

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवें इकाई से अधिक कुल करावण नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि यह अधिक होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। इसे ~~कर~~ रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है -



कर एवं लाभ की इकाई  
 उपयुक्त चित्र में  $Ox$  रेखा पर कर और लाभ की  
 इकाई तथा  $Oy$  रेखा पर उपयोगिता और अनुपयोगिता  
 का दिखाया गया है।  $UU$  एक सरकारी लाभ की  
 प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता को  
 व्यक्त करता है तथा  $DD$  एक कर की प्रत्येक इकाई  
 से क्रमशः बढ़ती हुई अनुपयोगिता को व्यक्त करता है।  
 शून्य एक इकाई को  $P$  बिन्दु पर काटता है।  
 यह Equilibrium point साम्य बिन्दु होता है।  
 बिन्दु पर सामाजिक लाभ अर्थात् अनुपयोगिता एवं  
 सामाजिक लागत अर्थात् उपयोगिता एक दूसरे के  
 बराबर होते हैं  $OM$  मात्रा से अधिक कर लेने  
 तथा लाभ करने से अनुपयोगिता अधिक और  
 उपयोगिता कम हो जाता है जो  $P_2M_2$  रेखा से  
 स्पष्ट है और  $OM$  से कम कर लेने तथा लाभ  
 करने से उपयोगिता अधिक और अनुपयोगिता कम  
 हो जाती है जैसा कि  $P_1M_1$  रेखा से स्पष्ट है।  
 अतः  $OM$  कर और लाभ की आदर्श मात्रा से

ही सामाजिक लाभ अधिकतम हो सकता है।  
 अधिकतम सामाजिक लाभ की कारणा कुल सामाजिक  
 लाभ तथा कुल सामाजिक लाभ वक्र अंतर की स्पष्ट  
 किया जा सकता है। अधिकतम सामाजिक लाभ उस  
 बिन्दु पर प्राप्त होता है जहाँ कुल सामाजिक लाभ तथा कुल  
 सामाजिक लाभ का अंतर सबसे अधिक है। इसे  
 चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -



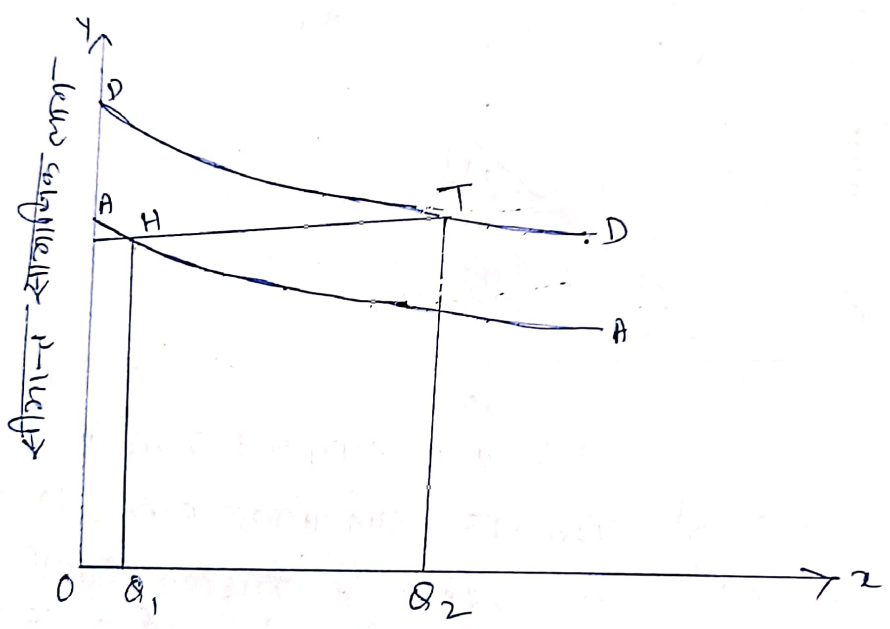
कर तथा व्यय की ईकाईयाँ

उपरोक्त चित्र में TSB वक्र सार्वजनिक व्यय से प्राप्त कुल सामाजिक लाभ को दर्शाता है जिसका ढाल ऊपर की ओर उठता हुआ प्राप्त होता है जो दर्शाता है कि जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जाती है कुल सामाजिक लाभ बढ़ता जाता है किन्तु एक बिन्दु के बाद व्यय लगता है। इसके विपरीत TSS वक्र कर से उत्पन्न कुल सामाजिक लागत को प्रदर्शित करता है जो व्यय की मात्रा के साथ कुल लागत बढ़ता जाता है किन्तु एक बिन्दु के बाद कुल लागत घटती गति से बढ़ने लग जाता है।  
 यहाँ TSB तथा TSS वक्र का अंतर शुद्ध सामाजिक लाभ को दर्शाता है जो MN रेखा से दर्शाया गया है।

कारण: सरकार को 0Q मात्रा में व्यय करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए व्यय करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना पड़ता है -

(1) प्रत्येक व्यय से सीमित उपयोगिता समान रहनी चाहिए। अर्थात् किसी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय करना और दूसरी मद की उपेक्षा कर देना सामाजिक लाभ में वृद्धि नहीं की जा सकती।

(2) लाभ रेखा है कि उत्पादन बढ़े। इस चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं -



उपरोक्त चित्र में AA वक्र कृषि पर किया गया सामाजिक व्यय तथा DD वक्र सुरक्षा पर किए गए सामाजिक व्यय को दर्शाता है। अर्थात् से प्राप्त सीमित सामाजिक लाभ की स्थिति  $HQ = TQ_2$  होगा। अतः कृषि पर  $0Q_1$  तथा सुरक्षा पर  $0Q_2$  मात्रा में व्यय किए जाए तो दोनों से सीमित सामाजिक लाभ समान मात्रा में प्राप्त होगा और यही अधिकतम सामाजिक लाभ होगा।

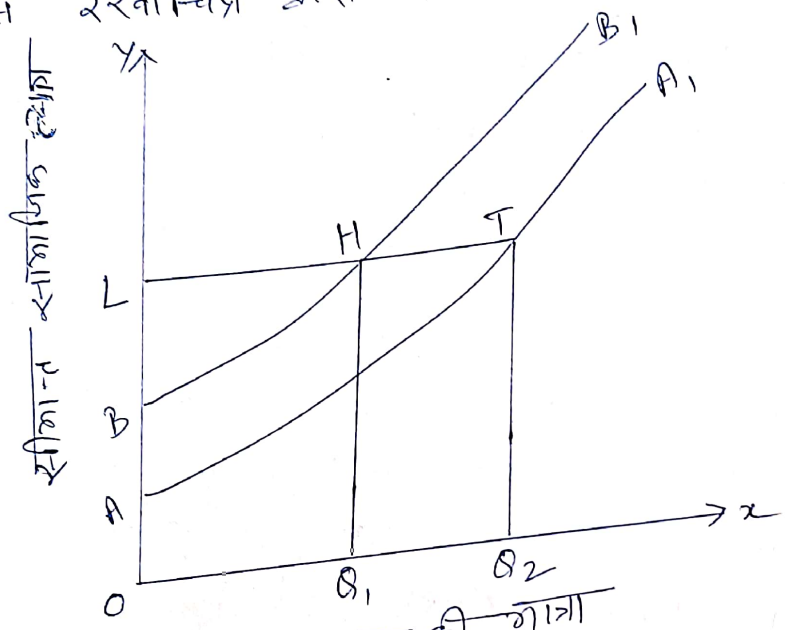
अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए कर लगाते समय भी निम्न बातों का ध्यान में रखना

करा...  
करा...  
करा...

करा...  
करा...

करा... कर देने की शक्ति में कायदा पर किया जाना चाहिए। ताकि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कर का भार पड़े।

- करा... के समान काम करने वाले व्यक्तियों की इच्छा से योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े। इसे रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है -



उपरोक्त चित्र में  $AA_1$  तथा  $BB_1$  वक्र A तथा B व्यक्तियों द्वारा कर अदा करने से सीमांत सामाजिक लाभ को प्रदर्शित करता है। कुल लाभ उसी अवस्था में अधिक होगा। अतः सरकार A व्यक्ति पर  $OQ_2$  तथा B व्यक्ति पर  $OQ_1$  कर वसूल कर लगभगी व्ययों पर  $TQ_2 = HQ_1$ ।

अर्थात् इस सिद्धान्त का बहुत अधिक महत्व है किन्तु व्यवहार में अनेक कठिनाईयों उत्पन्न होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं -  
 सर्वप्रथम करो से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता तथा राजकीय व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का पता लगाना तथा इसके सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है।  
 सरकारी व्यय का उद्देश्य सामान्यता

भविष्य में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाता है, परन्तु लाभ को के लिए जो राशि संग्रह की जाती है, उसे वर्तमान में ही व्यय किया जाता है। इस प्रकार करो का प्रभाव तत्काल देखा जा सकता है जबकि लाभ का प्रभाव भविष्य में पड़ता है इसी स्थिति में जी करो की वर्तमान अनुपयोगिता तथा लाभ से भविष्य में मिलने वाली उपयोगिता का अनुमान लगाना कठिन कार्य है।

करारोपण द्वारा प्राप्त रकम के लाभ से समाज के कुछ वर्गों को लाभ होता है। इस लाभ को जी बीक बीक आपना कठिन कार्य है।

उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद बहुत दूर तक इस सिद्धान्त को अवहारिक रूप दिया जा सकता है। सरकार अपनी आर्थिक कतिपय पर विचार करते हुए समस्त अधिकांश सामाजिक लाभ का विशेष ख्याल रखने।

—X—

Dr Sandhya Rani  
Dept of Economics  
Maharaja College